हिन्दी दैनिक

पथ प्रवाह

RNI No.: UTTHIN/2011/39282

निर्भीक, निष्पक्ष, सच का प्रवाह

वर्ष:5 अंक:156 पृष्ठ:08 मुल्य:1 रूपये | pathpravah.com | हरिद्वार, शुक्रवार, 12 जून 2026

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने प्रस्तुत किया उत्तराखंड के विकास का रोडमैप

पथ प्रवाह, देहरादून/नई दिल्ली।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक में राज्य के विकास का रोड मैप प्रस्तुत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन से जुड़े विषयों पर विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था पर भी जोर दिया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित भारत-2047 के संकल्प का आधार हमारी मानव पूंजी है। इसी सोच के अनुरूप उत्तराखंड सरकार मानव संसाधन विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार और युवा सशक्तिकरण पर विशेष बल दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने प्रारंभिक बाल शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अनेक सुधार किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हजारों आंगनवाड़ी केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है, विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, वर्चुअल क्लासरूम तथा कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में भी शोध, नवाचार एवं उद्यमिता को नई दिशा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। ताकि युवाओं को रोजगार प्राप्त करने वाले के बजाय रोजगार सृजित करने वाला बनाया जा सके।

युवाओं को स्किल देने पर जोर

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसी उद्देश्य से प्रदेश में देवभूमि उद्यमिता विकास योजना, स्टार्टअप प्रोत्साहन कार्यक्रम, उद्योग-अकादमिक सहयोग तथा आईटीआई संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित करने जैसी पहल लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 'विकसित भारत के लिए विकसित उत्तराखंड' के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए विगत वर्षों में 30 से अधिक विभिन्न नई नीतियों के माध्यम से कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सेवा क्षेत्र को एकीकृत करते हुए विकास के एक समन्वित मॉडल के तौर पर विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके परिणाम राज्य की अर्थव्यवस्था, निवेश, रोजगार एवं प्रति व्यक्ति आय में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

उत्तराखंड को राष्ट्रीय मॉडल बनाने का प्रयास

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक खेती, बागवानी, औषधीय पौधों, योग एवं वेलनेस, पर्यटन और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को भविष्य के विकास इंजन के रूप में विकसित करने का प्रयास कर रही है। साथ ही उत्तराखंड को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, वेलनेस इकोनॉमी तथा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के राष्ट्रीय मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को देश की पर्यावरणीय एवं आध्यात्मिक धरोहरों के संरक्षण, संवर्धन एवं संवहन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त है। हिमालय, गंगा, यमुना एवं विशाल वन क्षेत्र केवल उत्तराखंड की ही धरोहर नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की अमूल्य संपत्ति हैं। इसीलिए हिमालयी राज्यों के लिए जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण, आपदा प्रबंधन, कार्बन न्यूट्रैलिटी, ग्रीन एनर्जी एवं पर्वतीय अवसंरचना विकास से जुड़े विषयों पर विशेष नीति समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय व्यवस्था पर विचार करना वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है।

सुशासन और तकनीकी नवाचार

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड ने सुशासन और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में भी कई महत्वपूर्ण पहल प्रारम्भ की हैं। देवभूमि परिवार पहचान योजना, खनन क्षेत्र में डिजिटल निगरानी प्रणाली, भूमि उपयोग परिवर्तन प्रक्रिया का ऑनलाइन सरलीकरण तथा महिला सशक्तिकरण से जुड़े सुधारों ने शासन व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया है। इसी तरह उत्तराखंड नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति कर रहा है। पीरूल आधारित ऊर्जा उत्पादन जैसे नवाचार पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए विश्व की अग्रणी शक्तियों में अपना स्थान और अधिक सुदृढ़ करने की ओर अग्रसर है। उत्तराखंड भी इस राष्ट्रीय अभियान में अपनी पूर्ण प्रतिबद्धता, ऊर्जा और सामर्थ्य के साथ योगदान देता रहेगा।

कुंभ और नंदा राजजात का निमंत्रण

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 12 वर्ष के रिकॉर्ड कार्यकाल पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सर्वाधिक अवधि तक जनादेश प्राप्त कर निरंतर राष्ट्रसेवा का कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री सहित नीति आयोग के सभी सदस्यों को उत्तराखंड में अगले वर्ष आयोजित होने वाले कुम्भ मेला और नन्दा राजजात यात्रा का निमंत्रण दिया।

राज्यसभा की 21 सीटों पर निर्विरोध चुनाव में भाजपा के 12, कांग्रेस के चार उम्मीदवार निर्वाचित

नयी दिल्ली। देश के 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए हो रहे द्विवार्षिक चुनाव में 21 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किये गये हैं। इसके अलावा तीन राज्यों की तीन राज्यसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

झारखंड की दो तथा मिजोरम की एक सीट पर 18 जून को मतदान होगा। झारखंड की दो सीटों के लिए तीन उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें झामुमो के बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के प्रणव झा तथा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी शामिल हैं। वहीं मिजोरम की एक सीट के लिए एमएनएफ के निवर्तमान सदस्य के. वनलालवेना और जेडपीएम समर्थित लालह्मिंगलियाना चुनाव मैदान में हैं।

राज्यसभा की जिन 21 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, उनके लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि गुरुवार थी। आठ राज्यों की 21 सीटों के लिए 21 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए और उनके विरुद्ध कोई अन्य प्रत्याशी मैदान में नहीं होने के कारण उन्हें निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। मध्य प्रदेश

में तीन सीटों के लिए चार उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किए थे लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन पत्र निरस्त किए जाने के बाद तीन सीटों के लिए केवल तीन उम्मीदवार ही शेष बचे। इसके मद्देनजर तीनों को निर्वाचित घोषित कर दिया गया। सुश्री नटराजन ने नामांकन पत्र रद्द किए जाने के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की है, जिस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। निर्विरोध निर्वाचित 21 उम्मीदवारों में भाजपा के 12, कांग्रेस के चार, तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) के तीन, जनसेना पार्टी का एक तथा नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) का एक उम्मीदवार शामिल है।

विकसित भारत का संकल्प हर राज्य, जिले, ब्लॉक, गांव का सामूहिक संकल्प बने: मोदी

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को यहां नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को प्रत्येक राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का सामूहिक संकल्प बनाने का आह्वान किया।

मोदी ने नीति आयोग की संचालन परिषद की 11 वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए देश की युवा शक्ति को सबसे बड़ी पूंजी और ऐतिहासिक अवसर बताते हुए राज्यों से युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार शिक्षित प्रशित करने पर बल दिया। इस वर्ष की बैठक का विषय था, 'विकसित भारत-2047 के लिए समावेशी मानव विकास।' बैठक में उपस्थित मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों ने मोदी को 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने पर बधाई दी। नीति आयोग की विज्ञप्ति के अनुसार चर्चा के दौरान उन्होंने वैश्विक भू-राजनीतिक संकटों का सामना करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने तथा भारत की विकास गति को बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार के साथ एकजुटता भी व्यक्त की। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित इस बैठक में सभी 28 राज्यों और पांच केंद्रशासित प्रदेशों की भागीदारी रही और पहली बार सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री नीति आयोग की संचालन परिषद की बैठक में शामिल हुए।

केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व उनके उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री और प्रशासकों द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जब दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अनिश्चितता और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हैं, तब भारत की विकास गाथा विश्व को प्रेरित कर रही है। उन्होंने आत्मनिर्भरता के संकल्प को और मजबूत करने तथा विशेष रूप से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने और लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया। सहकारी संघवाद के महत्व को रेखांकित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केंद्र और राज्यों को मिलकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का विजन प्रत्येक राज्य, जिले, ब्लॉक और गांव का सामूहिक संकल्प बनना चाहिए। देश की देश में युवा आबादी की उच्च अनुपात को जनसांख्यिकीय शक्ति बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि लगभग 70 करोड़ नागरिक 25 वर्ष से कम आयु के हैं और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने इसे जनसांख्यिकीय लाभांश बताते हुए राज्यों से आग्रह किया कि शिक्षा, कौशल विकास और क्षमता निर्माण के माध्यम से इसे विकास लाभांश में परिवर्तित किया जाये। हाल ही में विभिन्न देशों के साथ संपन्न व्यापार समझौतों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने राज्यों से युवाओं और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए अवसर सृजित करने तथा इन समझौतों से मिलने वाले लाभों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने का आह्वान किया।

जनपद के 53 केंद्रों पर 14 जून को आयोजित होगी चस्स्स्ष्ट स्नातक स्तरीय परीक्षा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (चस्स्स्ष्ट) द्वारा दिनांक 14 जून 2026 को आयोजित की जाने वाली स्नातक स्तरीय पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के सफल एवं सुचारु संचालन के संबंध में विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में उन्होंने सभी नोडल/जोनल/सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराया गया कि उक्त परीक्षा जनपद हरिद्वार के 53 परीक्षा केंद्रों पर प्रातः 11:00 बजे से अपराह्न 01:00 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने हेतु व्यापक प्रशासनिक एवं पुलिस व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्देश दिए कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर मूलभूत सुविधाएं जैसे पेयजल, स्वच्छता, विद्युत, बैठने की समुचित व्यवस्था एवं अभ्यर्थियों के लिए सुगम प्रवेश-निकास सुनिश्चित किया जाए। सभी केंद्रों पर समय से पूर्व तैयारी पूर्ण कर ली जाए तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

परीक्षा के सफल संचालन हेतु जनपद स्तर पर नोडल अधिकारी (परीक्षा), जोनल मजिस्ट्रेट एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो आपसी समन्वय स्थापित करते हुए परीक्षा को सकुशल संपन्न कराएंगे। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु प्रत्येक केंद्र पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित की जाए। संवेदनशील केंद्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। परीक्षा से पूर्व से ही होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, कोचिंग संस्थानों आदि की सघन जांच की जाएगी, ताकि किसी भी प्रकार की नकल/अनुचित गतिविधियों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

उन्होंने सभी को स्पष्ट निर्देश दिए है कि परीक्षा से एक दिन पूर्व प्रत्येक परीक्षा केंद्र का पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा तथा सीसीटीवी, जैमर एवं अन्य सुरक्षा उपकरणों की कार्यशीलता की जांच सुनिश्चित की जाएगी। परीक्षा दिवस पर प्रातः 08:00 बजे से केंद्र परिसरों की सघन चेकिंग, सैनिटाइजेशन किया जाएगा।

उन्होंने अभ्यर्थियों की प्रवेश के समय सघन तलाशी की व्यवस्था रहेगी, जिसमें पुलिस बल एवं महिला कर्मियों की तैनाती की जाएगी। सभी अभ्यर्थियों का प्रवेश केवल मुख्य द्वार से ही कराया जाएगा तथा अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान धारा 163 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ एकत्र न होने दी जाए। साथ ही परिवहन, चिकित्सा एवं आपातकालीन सेवाओं को भी अलर्ट मोड में रखा जाएगा।

बैठक में सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपनी-अपनी तैयारियों की जानकारी प्रस्तुत की तथा परीक्षा को शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने हेतु पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने सभी अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों का समयबद्ध एवं जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की दीपम रामचंद्र सेठ, अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी आर के सिंह, एसपी ट्रैफिक निशा यादव, नगर मजिस्ट्रेट हर गिरी, नगर आयुक्त रुड़की गोपाल राम बिनवाल, उप जिलाधिकारी हरिद्वार योगेश मेहरा, मुख्य कोषाधिकारी अजय कुमार, सहायक परियोजना निर्देशक नलिनीत घिल्डियाल, जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) अमित कुमार चन्द सहित जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी सहित सभी परीक्षा केंद्रों हेतु तैनात ऑब्जर्वर उपस्थित रहे।

एक नजर

एक दिन में तैयार की सीवरेज के लिए खोदी गई 167 मीटर सड़क

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार शहर के अंतर्गत सीवरेज कार्य हेतु खोदी गई सड़कों से क्षेत्रीय जनता, व्यापारियों को हो रही परेशानी के दृष्टिगत जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने चल रहे निर्माण कार्यों को त्वरित गति से दिन रात कार्य करते हुए पूर्ण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं कांट्रेक्टर को दिए थे। परियोजना प्रबंधक निर्माण एवं अनुरक्षण इकाई गंगा उत्तराखंड पेयजल निगम मिनाक्षी मित्तल ने अवगत कराया है कि जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुपालन में केएफडब्ल्यू वित्त पोषित हरिद्वार जलोत्सारण योजना पैकेज 01 एवं पैकेज 02 के अंतर्गत कराए जा रहे सड़क पुनर्निर्माण संबंधी कार्य जिसके तहत 10 जून को किए गए निर्माण कार्यों का विवरण निम्नवत है जिसमें- पैकेज 01 के अंतर्गत हैं मंदिर से अमृत गंगा अपार्टमेंट बी टी रोड वर्क 60 मीटर कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पैकेज 02 के अंतर्गत गणपतिधाम फेस 2 सीसी रोड 35 मीटर, गणपतिधाम फेस 3 पावर ब्लॉक 52 मीटर, शिवानीपुरम सीसी रोड 20 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा कुल 107 मीटर कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सड़कों का कार्य दिन-रात त्वरित गति से किए जा रहे है।

उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं

पथ प्रवाह, हरिद्वार। उत्तराखण्ड में उपाध्यक्ष समाज कल्याण योजनाएं एवं अनुश्रवण समिति (राज्य मंत्री स्तर) एवं पूर्व विधायक देशराज कर्णवाल ने जनपद हरिद्वार के ग्राम मतलबपुर के प्राइमरी स्कूल में आयोजित बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर बहुद्देशीय शिविर में प्रतिभाग किया। यहां ग्रामवासियों ने उनका ढोल-नगाड़ों और फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। उपाध्यक्ष देशराज कर्णवाल ने कार्यक्रम के दौरान स्थानीय ग्रामीणों एवं लाभार्थियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। उपाध्यक्ष ने सहायक समाज कल्याण अधिकारी रुड़की को निर्देश दिए कि कार्यक्रम से एक घंटा पूर्व पहुंचकर जनता की समस्याएं पंजीकृत करें एवं उनका प्राथमिकता से निस्तारण कराएं। श्री कर्णवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सरकार का संकल्प है कि समाज कल्याण की सभी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सरलता से पहुंचे। उपाध्यक्ष का यह शिविर कार्यक्रम मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में अनुमोदित था। कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड़की को नोडल अधिकारी नामित किया गया था। थाना अध्यक्ष झबरेड़ा द्वारा सुरक्षा व्यवस्था एवं नगर आयुक्त रुड़की द्वारा स्थल व्यवस्था सुनिश्चित की गई।

15 जून से जनपद की 318 ग्राम पंचायतों में लगेंगे फाइनेंशियल इन्क्लूजन सैचुरेशन कैंप

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र समेत विभिन्न बैंकों, सरकारी विभागों तथा संबंधित हितधारकों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया।

बैठक में जनपद स्तर पर अभियान के सफल संचालन हेतु विस्तृत कार्ययोजना एवं रूपरेखा पर चर्चा की गई। वित्तीय सेवाएं विभाग (DFS), भारत सरकार के निर्देशानुसार जनपद हरिद्वार की सभी 318 ग्राम पंचायतों में दिनांक 15 जून 2026 से 15 जुलाई 2026 तक 'फाइनेंशियल इन्क्लूजन सैचुरेशन कैंप' का आयोजन किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य प्रत्येक पात्र ग्रामीण परिवार को बैंकिंग एवं सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ते हुए वित्तीय समावेशन को शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना है। जिलाधिकारी ने सभी बैंकों एवं संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले कैंपों में पात्र व्यक्तियों को बैंक खाते खोलने, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (PMJJBY, PMSBY, APY) से जोड़ने, डिजिटल बैंकिंग, आधार सीडिंग, नामांकन, सीकेवाईसी, पुनः केवाईसी सहित अन्य वित्तीय सेवाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने सभी संबंधित संस्थाओं से आपसी समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

बैठक में उपस्थित मुख्य विकास अधिकारी डॉ ललित नारायण मिश्र ने ग्राम पंचायत स्तर पर अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करने तथा वित्तीय समावेशन के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए। एलडीएम दिनेश कुमार गुप्ता द्वारा जनपद के सभी बैंकों से अनुरोध किया गया है कि वे इस महत्वाकांक्षी अभियान में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय उद्देश्य को सफल बनाने में अपना योगदान दें। इस दौरान जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

सीएससी और पेट्रोल पंप के खातों को म्यूल अकाउंट बनाकर साइबर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

हरिद्वार पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है, जो सीएससी सेंटरों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खातों का इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को खपाने के लिए कर रहा था। कोतवाली लक्सर पुलिस, सीआईयू रुड़की और साइबर सेल की संयुक्त कार्रवाई में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी विशेष एपीके फाइलों और क्यूआर कोड के माध्यम से साइबर ठगी को अंजाम देते थे। ठगी से प्राप्त रकम सीधे सीएससी सेंटर संचालकों और अन्य प्रतिष्ठानों के खातों में ट्रांसफर कराई जाती थी, जिससे धन के वास्तविक स्रोत को छिपाया जा सके। इसके बाद नकद निकासी कर विभिन्न कैश डिपॉजिट मशीनों के जरिए रकम अन्य खातों में जमा कर दी जाती थी, जिससे धन की ट्रेल टूट जाती थी। गिरोह के सदस्य ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों को भावनात्मक कहानियां सुनाकर अपने जाल में फंसाते थे। कभी वाहन चालान भरने की मजबूरी तो कभी कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का हवाला देकर लोगों से नकद धनराशि हासिल की जाती थी। बाद में उन्हीं लोगों के खातों में संदिग्ध लेनदेन होने के कारण खाते फ्रीज हो जाते थे। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम दाबकी कला निवासी मनीष कुमार और सुशील कुमार ने कोतवाली लक्सर में शिकायत दर्ज कराई। दोनों ने आरोप लगाया कि कुछ व्यक्तियों ने वाहन चालान और बीमारी का बहाना बनाकर उनसे क्रमशः 91 हजार और 80 हजार रुपये नकद लिए। बाद में उनके बैंक खाते फ्रीज हो गए, जिससे उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का पता चला। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और मोबाइल फोन की व्हाट्सएप चैट के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। जांच के दौरान विभिन्न फतू कोड और संदिग्ध लेनदेन से जुड़े स्क्रीनशॉट भी बरामद हुए। पुलिस ने 11 जून को दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 1 लाख 48 हजार रुपये नकद तथा घटना में प्रयुक्त पोको ब्लू मोबाइल फोन बरामद किया। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान अंकित चौहान (29 वर्ष) पुत्र मुल्तान सिंह तथा विशाल चौहान (28 वर्ष) पुत्र पवन सिंह, दोनों निवासी ग्राम शाहपुर, थाना बेहट, जिला सहारनपुर के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपितों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई कर उनका चालान कर दिया है, जबकि गिरोह से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपने बैंक खाते, क्यूआर कोड या वित्तीय संसाधनों का उपयोग न करने दें तथा किसी भी साइबर धोखाधड़ी की सूचना तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या नजदीकी पुलिस थाने को दें।

एक नजर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति से आगे बढ़कर प्रगति को चुना: सुनील सैनी

पथ प्रवाह, हरिद्वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने पर सुनील सैनी राज्य मंत्री ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों का विश्वास, एक प्रधानसेवक का संकल्प और विकसित भारत की ओर बढ़ता एक राष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने राजनीति से आगे बढ़कर प्रगति को चुना है, तुष्टिकरण से आगे बढ़कर सशक्तिकरण को चुना है और आशाओं को उपलब्धियों में बदला है। 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने से लेकर नारी शक्ति को नए अवसर देने तक, देवालय से शौचालय तक, चंद्रयान 3 से वसुधैव कुटुम्बकम् तक, यह यात्रा एक ऐसे भारत की है जिसने स्वयं पर विश्वास करना सीखा है। सुनील सैनी ने कहा कि इन 12 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के विकास , गरीबों और देश के लिए समर्पित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद से देवभूमि उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में निरंतर विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। सुनील सैनी ने प्रधानमंत्री को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। यह भी कहा अयोध्या में श्री राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, केदारनाथ धाम पुनर्निर्माण जैसे कार्यों को देश के सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। कहा कि युग पुरुष देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद सदैव हम सभी भारतवासियों को मिलता रहे।

लंबगांव हत्याकांड : 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच तेज

पथ प्रवाह, नई टिहरी। टिहरी जनपद के चर्चित लंबगांव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में दो और आरोपियों–सचिन पंवार और सुमित प्रसाद–को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों की संलिप्तता जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर सामने आई। इससे पहले भी इस हत्याकांड में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। ताजा कार्रवाई के बाद अब कुल चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्वेता चौबे ने बताया कि मामले की निष्पक्ष और गहन विवेचना जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि घटना के पीछे की पूरी साजिश और कारणों का खुलासा किया जा सके। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।

मेयर ने किया त्रिमूर्ति नगर चौराहे एवं मंदिर के सौंदर्यीकरण कार्य का उद्घाटन

पथ प्रवाह, हरिद्वार। मेयर किरण जैसल ने वार्ड 44 त्रिमूर्ति नगर में पार्षद अहसान अंसारी के प्रस्ताव पर कराए गए त्रिमूर्ति नगर चौराहे के निर्माण कार्य तथा त्रिमूर्ति मंदिर के बाहरी हिस्से के सौंदर्यीकरण कार्य का विधिवत उद्घाटन किया।

मेयर किरण जैसल ने कहा कि शहर के सभी वार्डों में प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक स्थलों एवं धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण से क्षेत्र की पहचान मजबूत होती है तथा नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होती हैं। पार्षद अहसान अंसारी ने मेयर का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास एवं सौंदर्यीकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि त्रिमूर्ति नगर चौराहे के निर्माण और मंदिर के बाहरी सौंदर्यीकरण से क्षेत्र की सुंदरता में वृद्धि होगी तथा स्थानीय लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस अवसर पर मंडी समिति ज्वालापुर के सचिव लवकेश गिरी, नगर निगम के सेनेटरी इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह, रणवीर सिंह सैनी, सरिता सिंह, हाजी शहाबुद्दीन, राजवीर सिंह, चंद्रपाल सिंह, संजय मेहता, पर्यावरण पर्यवेक्षक अखिल कुमार, कुसुम पाल, इमरान मंसूरी, उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य सज्जाद अहमद, गुलाम साबिर, जमशेद खान, राव आबाद, वाजिद अली, दानिश अंसारी, पार्षद प्रतिनिधि जाफिर अंसारी, पंडित अनुराग शर्मा, राकेश सैनी सहित अनेक क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

स्मार्ट मीटर के विरोध में किया अधिशासी अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं के घर, दुकान, प्रतिष्ठान में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर के विरोध में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम स्थित विद्युत विभाग कार्यालय का घेराव किया। विरोध करने पहुंचे कार्यकर्ताओं का गुस्सा तब और अधिक बढ़ गया जब अधिशासी अभियंता अपने कार्यालय में नहीं मिले। कार्यकर्ताओं ने कार्यालय में नारेबाजी शुरू कर दी। जिसके बाद सहायक अभियंता मौके पर पहुंचे।

युवा कांग्रेस पूर्व जिलाध्यक्ष कैश खुराना, प्रदेश महासचिव दिव्यांश अग्रवाल ने कहा कि अधिकारी कार्यालय पर नहीं बैठते। स्मार्ट मीटर लगाकर जनता का शोषण किया जा रहा है। स्मार्ट मीटर से बहुत अधिक बिल आ रहा है जिसके कारण उपभोक्ता परेशान हैं। उन्होंने कहा कि विभाग स्मार्ट मीटर लगाना बंद करे। लोगों की आय कम है और बिल अधिक आता है। नितिन तेश्वर, महानगर उपाध्यक्ष परितोष त्यागी ने कहा कि भाजपा और विभाग की हठधर्मिता जनता पर भारी पड़ रही है। लोग स्मार्ट मीटर लगवाना नहीं चाहते और सरकार जबरदस्ती लगा रही है। संजय सैनी, समर्थ अग्रवाल ने कहा कि बिना जांच के स्मार्ट मीटर थोपे जा रहे हैं। आरटीआई में इसका खुलासा हुआ है। स्मार्ट मीटर नहीं चीटर हैं। जनता की जेब पर डाका डाला जा रहा है। इस अवसर पर पार्षद अकरम अंसारी, इदरीश मंसूरी, रविश भटीजा, विशाल प्रधान, मयंक सिंह, मनोज जाटव, कार्तिक शर्मा, अयान सैफी, लक्की महाजन, नमन अग्रवाल, डॉ. मेहरबान, सुमित, जितेंद्र चौधरी, विशाल, आकाश, सिद्धांत चौहान, प्रतीक आदि मौजूद रहे।

पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ को भाजपा में वापसी की आस, हाई कोर्ट से दो मुकदमे खारिज होने का दावा

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

ज्वालापुर सीट से पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने दावा किया है कि उनके खिलाफ विभिन्न थानों में दर्ज चार मुकदमों में से दो को नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि शेष दो मामलों में भी जांच के बाद वह निर्दोष साबित होंगे और सच्चाई की जीत होगी।

प्रेस क्लब में गुरुवार को पत्रकारों से वार्ता करते हुए सुरेश राठौड़ ने कहा कि कि वर्ष 2025 में उनके खिलाफ थाना बहादराबाद में दर्ज एफआईआर संख्या 534/2025 तथा थाना झबरेड़ा में दर्ज एफआईआर संख्या 356/2025 को लेकर उनके अधिवक्ताओं वैभव सिंह और एस.के. शांडिल्य द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने दोनों मुकदमों को खारिज कर दिया है।

जांच में कर रहे सहयोग

सुरेश राठौड़ ने बताया कि नेहरू कॉलोनी थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर संख्या 0420/2025 तथा डालनवाला थाना क्षेत्र में दर्ज एफआईआर संख्या 0004/2025 के मामलों में वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं।

उनका कहना है कि उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई ऑडियो या वीडियो प्रसारित नहीं की है और जांच में उनकी भूमिका स्पष्ट हो जाएगी। पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि सहारनपुर निवासी उर्मिला सनावर ने उन्हें परिवार का सदस्य बनाकर विश्वास में लिया और देर रात उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर साजिशन उसे मीडिया में प्रसारित किया, जिससे उनकी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में उनका कोई रोल नहीं था।

उम्मीद भाजपा हाईकमान निष्कासन पर करेगा पुनर्विचार

सुरेश राठौड़ ने कहा कि इस विवाद के चलते भाजपा नेतृत्व ने उनके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई की थी। अब जब दो मामलों में उन्हें राहत मिली है, तो उन्हें उम्मीद है कि भाजपा हाईकमान पूरे प्रकरण का संज्ञान लेते हुए उनके निष्कासन पर पुनर्विचार करेगा और उन्हें पार्टी में फिर से स्थान मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उनके कारण भाजपा नेताओं, विशेष रूप से दुष्यंत कुमार गौतम, महेन्द्र भट्ट अथवा अन्य नेताओं को किसी प्रकार की असहजता हुई हो तो वह इसके लिए खेद प्रकट करते हैं।

कलियर से अपहरण किया गया सात माह का मासूम बरामद, भीख मंगवाने की साजिश नाकाम

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जनपद हरिद्वार के थाना पिरान कलियर दरगाह परिसर से अपहृत सात माह के मासूम बच्चे को पुलिस ने महज चार दिनों के भीतर सकुशल बरामद कर एक महिला समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपितों ने बच्चे का अपहरण उसे गोद में लेकर भीख मांगने और अधिक पैसे कमाने की नीयत से किया था।

जानकारी के अनुसार बीती 7 जून को बिहार निवासी कलसूम खातून अपने परिवार के साथ दरगाह परिसर में मौजूद थीं। इसी दौरान नमाज के समय उनके सात माह के नाती मोहम्मद अली रजा का अपहरण हो गया। घटना की सूचना मिलते ही थाना पिरान कलियर में मुकदमा दर्ज किया गया और मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने तत्काल विशेष टीम गठित कर बच्चे की सकुशल बरामदगी के निर्देश दिए। पुलिस ने जांच के दौरान दरगाह परिसर, रुड़की-कलियर मार्ग, बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और आसपास के बाजारों में लगे करीब 250 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। फुटेज में एक विकलांग महिला और उसके साथ एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया। महिला की वैशाखियां और मासूम के दोनों हाथों में छह-छह उंगलियां पुलिस के लिए महत्वपूर्ण पहचान का आधार बनीं। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल सर्विलांस और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस गुरुवार को लक्सर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची, जहां एक विकलांग महिला बच्चे को गोद में लेकर भीख मांग रही थी। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया और महिला सहित उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि महिला बचपन से पोलियोग्रस्त है और अपने साथी समीर उर्फ सोनू के साथ रहती है। दोनों के पास आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं था। दरगाह में भीख मांगने के दौरान उन्होंने देखा कि छोटे बच्चों को गोद में लेकर भीख मांगने वालों को अधिक पैसे मिलते हैं। इसी लालच में उन्होंने बच्चे का अपहरण करने की योजना बनाई।

आरोपितों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने एक सप्ताह तक बच्चे और उसके परिवार पर नजर रखी। 7 जून की शाम मौका मिलते ही समीर उर्फ सोनू ने दरगाह परिसर से बच्चे का अपहरण कर लिया और उसे लंढौरा ले गया। इसके बाद दोनों बच्चे का इस्तेमाल कर भीख मांगने की तैयारी में थे। मासूम की सकुशल बरामदगी के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली और पुलिस का आभार जताया। मामले के सफल खुलासे पर एसएसपी हरिद्वार ने पुलिस टीम की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान समीर उर्फ सोनू उर्फ बड्डा (22 वर्ष), निवासी गोल्डन कॉलोनी, लंढौरा, थाना मंगलौर तथा एक 45 वर्षीय महिला अभियुक्ता के रूप में की है।

संपादकीय

मानसून सत्र और भारतीय राजनीति का समुद्र मंथन

जुलाई माह में संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। राजनीतिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि इस बार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक टकराहट देखने को मिल सकती है। महंगाई, बेरोजगारी, कृषि संकट, शिक्षा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न राज्यों की राजनीतिक परिस्थितियां ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है। पिछले सत्र में परिसीमन बिल सरकार संसद में पास नहीं करा पाई थी। बीते महीनों में जिस तरह से सरकार को आर्थिक संकट से गुजरना पड़ रहा है, विदेशी निवेशक शेयर बाजार से निवेश किया धन वापस निकाल रहे हैं। कच्चे तेल के आयात से सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। ऐसी स्थिति में सरकार मानसून सत्र में कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती है। देश में खाद्य पदार्थों, ईंधन और घरेलू जरूरतों की वस्तुओं की कीमतों को लेकर जनता के बड़े वर्ग में नाराजगी दिखाई दे रही है। किसान संगठन, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी), फसल खरीद और कृषि लागत जैसे मुद्दों पर आंदोलित हैं। वहीं नीट पेपर लीक से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और शिक्षा व्यवस्था को लेकर छात्र संगठनों की ओर से सड़क पर असंतोष व्यक्त किया जा रहा है। काकरोच के नाम पर युवा जेन-जी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहा है।

विपक्षी दलों द्वारा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सरकार के दबाव में काम करने के आरोप हैं। जबकि सरकार इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करती है। सरकार अपने कार्यकाल में हुए विकासकार्यों, कल्याणकारी योजनाओं तथा आर्थिक उपलब्धियों को सामने रखती है। राजनीतिक दलों के बीच बढ़ती बयानबाजी ने संसद के आगामी सत्र को और महत्वपूर्ण बना दिया है। एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही संसद सत्र के पहले अपने-अपने राजनीतिक समीकरण मजबूत करने में जुटे हुए हैं। क्षेत्रीय दलों की भूमिका इस बार विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि संसद का मानसून सत्र आने वाले विधानसभा चुनावों और भविष्य की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा तय करने में यह मानसून सत्र सरकार के लिए संकटभरा हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति को यदि समुद्र मंथन की उपमा दी जाए तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। समुद्र मंथन में जिस प्रकार देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष के साथ-साथ सहयोग भी था, उसी प्रकार भारतीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। उस पौराणिक कथा में पहले विष निकला और अंत में अमृत प्राप्त हुआ था। लोकतंत्र के इस राजनीतिक मंथन से मानसून सत्र में कौन लाभान्वित होगा और किसे राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा, इसका उत्तर भविष्य के गर्भ में छिपा है।

फिलहाल इतना स्पष्ट है कि मानसून सत्र केवल विधायी कार्यवाही का मंच नहीं रहेगा, बल्कि यह सरकार की नीतियों, विपक्ष की रणनीति और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका पर व्यापक राजनीतिक बहस का केंद्र बनने जा रहा है। इस राजनीतिक समुद्र मंथन का परिणाम क्या होगा, इसका निर्णय अंततः जनता और लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं ही तय करेंगी। जिस तरह से सत्ता पक्ष ने लोकसभा एवं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 6 सांसदों इसके बाद टीएमसी के सांसदों को पार्टी से अलग होकर अलग गुट बनाने या सांसदों से इस्तीफा दिलवाकर विपक्ष को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। उसका स्पष्ट संकेत है, मानसून सत्र में सरकार कोई भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। इसके लिए सरकार किसी भी स्तर पर अपने आपको सुरक्षित करने का हरसंभव प्रयास कर रही है। इसका एक संदेश यह भी है, सरकार अंदर से कमजोर है। भाजपा के अंदर से भी असंतोष के स्वर उठने लगे हैं। ऐसी स्थिति में सरकार ने चारों ओर से सुरक्षित रहने के लिए घेराबंदी शुरु कर दी है।

मोदी युग : जनविश्वास, विकास और इतिहास के आईने में एक निष्पक्ष मूल्यांकन

विनोद कुमार सिंह 'तकियावाला'

10 जून 2026 भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव के रूप में दर्ज हो गया। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबे समय तक देश का नेतृत्व करने वाले नेता बन गए। 4,399 दिनों के कार्यकाल के साथ उन्होंने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के 4,398 दिनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। स्वाभाविक रूप से इस उपलब्धि को भारतीय राजनीति की एक बड़ी घटना माना जा रहा है।किंतु लोकतंत्र में केवल रिकॉर्ड ही इतिहास नहीं बनाते, बल्कि इतिहास इस बात का भी मूल्यांकन करता है कि किसी नेता ने अपने समय की चुनौतियों का सामना किस प्रकार किया और राष्ट्र की दिशा को किस हद तक प्रभावित किया।यहीं से मोदी युग के मूल्यांकन की वास्तविक शुरुआत होती है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजनीतिक जीवन भारतीय लोकतंत्र की संभावनाओं का प्रतीक है। एक साधारण परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना और लगातार तीन बार जनादेश प्राप्त करना स्वयं में असाधारण उपलब्धि है। वर्ष 2014 में जब उन्होंने सत्ता संभाली, तब देश भ्रष्टाचार, नीतिगत गतिरोध, आर्थिक सुस्ती और प्रशासनिक अक्षमता के आरोपों से घिरा हुआ था। जनता परिवर्तन चाहती थी और मोदी उस परिवर्तन के प्रतीक बनकर उभरे।पिछले बारह वर्षों में सरकार ने कल्याणकारी योजनाओं का व्यापक विस्तार किया।प्रधानमंत्री आवास योजना,उज्ज्वला योजना, जनधन खाते,आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन,स्वच्छ भारत अभियान और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं ने करोड़ों लोगों तक सरकारी सहायता पहुंचाई।प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाई और बिचौलियों की भूमिका कम करने का प्रयास किया।ग्रामीण भारत में बिजली,सड़क,शौचालय और बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार हुआ। करोड़ों परिवार पहली बार औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़े। सरकार के समर्थक इसे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास का नया मॉडल बताते हैं।डिजिटल इंडिया अभियान ने शासन की कार्यशैली बदल दी। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत विश्व के अग्रणी देशों में शामिल हुआ। यूपीआई ने वित्तीय लेन-देन को सरल बनाया और तकनीक आधारित सेवाओं का विस्तार हुआ। स्टार्टअप इंडिया और नवाचार को प्रोत्साहन मिलने से भारत विश्व के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में गिना जाने लगा।विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं।चंद्रयान-3 की सफलता और अंतरिक्ष कार्यक्रमों ने भारत की वैज्ञानिक क्षमता को वैश्विक पहचान दिलाई।जी-20 की अध्यक्षता और वैश्विक मंचों पर बढ़ती सक्रियता ने भारत की अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा को मजबूत किया।राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में भी मोदी सरकार की नीतियों को व्यापक समर्थन मिला।सीमापार आतंकवाद के विरुद्ध सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक जैसे कदमों ने सरकार की निर्णायक छवि को मजबूत किया।अनुच्छेद 370 हटाने, तीन तलाक कानून और जीएसटी जैसे निर्णयों ने राजनीतिक विमर्श को नई दिशा दी। किसी भी लोकतंत्र में उपलब्धियों का मूल्यांकन केवल सरकारी दावों या समर्थकों की प्रशंसा से नहीं किया जा सकता। एक स्वतंत्र टिप्पणीकार की जिम्मेदारी उपलब्धियों के साथ- साथ चुनौतियों और प्रश्नों को भी सामने रखना है।भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है, लेकिन आम नागरिक का अनुभव केवल जीडीपी वृद्धि दर से तय नहीं होता। महँगाई,रोजगार, आय और जीवन स्तर उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण हैं।पिछले वर्षों में बेरोजगारी देश की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक बनी रही है।लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं और सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, लेकिन अवसर सीमित दिखाई देते हैं।भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और प्रश्नपत्र लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं में असंतोष भी पैदा किया है। विकसित भारत का सपना तब तक अधूरा रहेगा जब तक आर्थिक विकास बड़े पैमाने पर गुणवत्तापूर्ण रोजगार में परिवर्तित नहीं होता।मुद्रा योजना और स्वरोजगार आधारित पहलों को सरकार अपनी सफलता बताती है,किंतु अर्थशास्त्रियों का एक वर्ग यह प्रश्न भी उठाता है कि इन योजनाओं से उत्पन्न रोजगार कितने स्थायी और टिकाऊ हैं।इसी प्रकार बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों के बावजूद ऋण वसूली, एनपीए और वित्तीय अनुशासन के प्रश्न पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।

कृषि क्षेत्र में भी तस्वीर मिश्रित दिखाई देती है।किसान सम्मान निधि,सिंचाई योजनाओं और तकनीकी सुधारों ने सकारात्मक प्रभाव डाला है,लेकिन खेती की लागत, प्राकृतिक जोखिम और आय की अनिश्चितता आज भी किसानों की बड़ी चिंता है। कृषि कानूनों के विरुद्ध हुआ लंबा किसान आंदोलन इस बात का संकेत था कि आर्थिक सुधारों के साथ संवाद और सहमति भी उतनी ही आवश्यक है।मोदी युग का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक केंद्रीकरण का है।

समर्थक इसे मजबूत नेतृत्व कहते हैं,जबकि आलोचक संस्थागत संतुलन और लोकतांत्रिक विमर्श के कमजोर होने की आशंका व्यक्त करते हैं। मीडिया,जाँच एजेंसियों और विभिन्न संवैधानिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर समय-समय पर बहस होती रही है।लोकतंत्र की मजबूती केवल लोकप्रिय नेतृत्व में नहीं, बल्कि मजबूत संस्थाओं में भी निहित होती है।

कब थमेगी नन्हे हाथों से मजदूरी?

दिलीप कुमार पाठक

यह हमारे समाज का एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हम रोज देखते हैं और देखकर भी आगे बढ़ जाते हैं। एक तरफ वे बच्चे हैं जो सुबह-सुबह अच्छे कपड़े पहनकर, भारी-भारी बैग टांगे स्कूल जाते दिखते हैं। उनकी आंखों में ढेर सारे सपने होते हैं। वहीं दूसरी तरफ, ठीक उसी सड़क के पार किसी दुकान या ढाबे पर कोई छोटा सा बच्चा जूठे बर्तन साफ कर रहा होता है। उसके हाथ काम करते-करते थक चुके होते हैं और उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही डर होता है कि कहीं मालिक डांट न दे।

यह कहानी किसी एक शहर की नहीं है, हमारे आस-पास हर जगह यही हाल है। हर साल 12 जून को हम बाल श्रम निषेध दिवस मनाकर सोच लेते हैं कि हमने अपना फर्ज पूरा कर दिया, लेकिन सच तो यह है कि एक दिन तय कर देने से इन बच्चों की जिंदगी नहीं बदलती। बचपन का मतलब क्या होता है? बचपन यानी बिना किसी टेंशन के जीना, दोस्तों के साथ खेलना, मिट्टी में खेलना और बस मजे करना। लेकिन जब इन्हीं नन्हे हाथों में खिलौनों या किताबों की जगह भारी ईंटें, चाय के कप या साफ-सफाई का झाड़ू थमा दिया जाता है, तो सिर्फ एक बच्चा मजदूरी नहीं कर रहा होता बल्कि उस बच्चे का पूरा भविष्य हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। गरीबी और लाचारी इन बच्चों से हंसने-खेलने के दिन छीन लेती है। कारखानों के गंदे धुएं में, छोटे होटलों के बर्तनों के बीच और खेतों की तेज धूप में इनका बचपन इस तरह पिस जाता है कि ये बच्चे ढंग से मुस्कुराना तक भूल जाते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी छोटी सी उम्र में इन बच्चों को पढ़ाई छोड़कर काम पर क्यों लगना पड़ता है? इसका सबसे सीधा जवाब है - घर की गरीबी और लाचारी। जब किसी परिवार में दो वक्त के खाने का ठिकाना न हो, तो मजबूर होकर मां-बाप अपने ही बच्चे को थोड़े से पैसों के लिए काम पर भेज देते हैं। लेकिन इस लाचारी का सबसे गंदा फायदा हमारा पढ़ा-लिखा समाज उठाता है। छोटे दुकानदार, ठेकेदार और यहाँ तक कि बड़े घरों के लोग भी बच्चों को काम पर रखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे बहुत कम पैसों में बिना कोई नखरा किए दिन-रात काम करते हैं, और वे अपने हक के लिए कभी लड़ भी नहीं सकते। यह एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें फंसा हुआ बच्चा कभी पढ़-लिख नहीं पाता और बड़ा होकर भी इसी गरीबी में फंसा रह जाता है। कहने को तो हमारे देश में बाल मजदूरी के खिलाफ बहुत कड़े कानून बने हुए हैं। कानून कहता है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम कराना जुर्म है और हर बच्चे को स्कूल जाने का पूरा हक है। लेकिन सच यह है कि सिर्फ कागजों पर नियम बना देने से किसी गरीब का पेट नहीं भरता। जब तक जमीनी स्तर पर जाकर इन नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हर नुक्कड़ और चौराहे पर हमें कोई न कोई बच्चा गाड़ियां साफ करता हुआ या चाय की केतली थामे हुए ही दिखेगा। हम हमेशा सरकार और सिस्टम को कोसकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन समाज को बदलने की शुरुआत हमारे अपने घर और हमारी सोच से होती है। अगली बार जब आप किसी दुकान या होटल पर किसी बच्चे को काम करते देखें, तो वहां से चुपचाप चाय पीकर निकलने के बजाय दुकानदार से टोककर सवाल करें। अपने खुद के घरों में छोटे बच्चों से काम करवाना बिल्कुल बंद करें। अगर हम थोड़े भी सक्षम हैं, तो किसी एक गरीब बच्चे की पढ़ाई का खर्चा उठाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। बाल मजदूरी को रोकना सिर्फ कोई कानूनी नियम नहीं है, बल्कि यह हमारी इंसानियत का तकाजा है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता, जब तक उसकी आने वाली पीढ़ी अनपढ़ रहे।

बचपन को श्रम नहीं, शिक्षा, सुरक्षा और सम्मान का अधिकार मिले

ललित गर्ग

हर वर्ष 12 जून को मनाया जाने वाला बाल श्रम के विरुद्ध विश्व दिवस केवल एक औपचारिक दिवस नहीं, बल्कि मानवता के अंतःकरण को झकझोरने वाला अवसर है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया का कोई भी बच्चा मजदूर बनने के लिए पैदा नहीं होता। उसके हाथों में औजार, ईंट, बर्तन, हथौड़े, कूड़े की बोरी या कारखानों की मशीनें नहीं, बल्कि किताबें, खिलौने, रंग, सुनहले सपने और संभावनाएं होनी चाहिए। बचपन जीवन का वह स्वर्णिम काल है जिसमें व्यक्ति के व्यक्तित्व, संस्कार, शिक्षा और भविष्य की नींव रखी जाती है। यदि यही काल श्रम, शोषण और अभाव की भट्ठी में झोंक दिया जाए तो केवल एक बच्चे का नहीं, पूरे समाज और राष्ट्र का भविष्य अंधकारमय हो जाता है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन- आईअलओ द्वारा 2002 में शुरू किए गए इस दिवस का उद्देश्य बाल श्रम की भयावहता के प्रति वैश्विक चेतना जगाना और इसके उन्मूलन के लिए सामूहिक प्रयासों को गति देना है। वर्ष 2026 में भी यह दिवस ऐसे समय पर आ रहा है जब दुनिया तकनीकी विकास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आर्थिक प्रगति के नए आयाम छू रही है, लेकिन दूसरी ओर करोड़ों बच्चे आज भी शिक्षा और बचपन के अधिकार से वंचित हैं। यह विडम्बना मानव सभ्यता के सामने एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। जब हम किसी ढाबे, होटल, चाय की दुकान, कारखाने, गैरेज, ईंट-भट्ठे, खेत या ट्रैफिक सिग्नल पर किसी मासूम बच्चे को कठिन श्रम करते देखते हैं, तब अक्सर हमारी संवेदना कुछ क्षणों के लिए जागती है और फिर हम अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह है कि कब तक हम इस पीड़ा को सामान्य मानते रहेंगे? क्या हम उस बचपन की चीख नहीं सुन पा रहे जो अपने अधिकारों से वंचित होकर मजदूरी के अंधेरे में खो रहा है?

आज भी विश्व में करोड़ों बच्चे किसी न किसी रूप में बाल श्रम में संलग्न हैं। इनमें से बड़ी संख्या खतरनाक परिस्थितियों में काम करती है, जहां उनका शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास बाधित होता है। गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता, विस्थापन, तस्करी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थाएं बाल श्रम की प्रमुख वजहें हैं। परिवार की आर्थिक विवशताएं बच्चों को स्कूल की बजाय काम की दुनिया में धकेल देती हैं। लेकिन गरीबी का समाधान बच्चों से काम कराना नहीं, बल्कि परिवारों को सम्मानजनक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। बाल श्रम केवल आर्थिक समस्या नहीं है; यह मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। यह बच्चों से उनका बचपन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, आत्मविश्वास और भविष्य छीन लेता है। जो बच्चा विद्यालय में होना चाहिए, वह यदि कारखाने में है, तो यह केवल उस बच्चे की नहीं, पूरे समाज की विफलता है। बाल श्रम गरीबी का चक्र भी बनाए रखता है, क्योंकि अशिक्षित बच्चा बड़ा होकर कम आय वाले कार्यों तक सीमित रह जाता है और अगली पीढ़ी भी उसी अभाव में जीने को मजबूर होती है।

भारत सहित अनेक देशों में बाल श्रम रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईअलओ के कन्वेंशन 138 और कन्वेंशन 182 न्यूनतम कार्य आयु और बाल श्रम के सबसे खतरनाक रूपों पर रोक लगाने के लिए महत्वपूर्ण आधार प्रदान करते हैं। भारत में भी बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम तथा शिक्षा का अधिकार कानून मौजूद हैं। लेकिन कानूनों की प्रभावशीलता उनके कठोर और ईमानदार क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। कई बार कानूनी प्रावधान होने के बावजूद बाल श्रम छिपे हुए रूपों में जारी रहता है। आज आवश्यकता केवल कानून बनाने की नहीं, बल्कि उन्हें सामाजिक आंदोलन का स्वरूप देने की है।

बाल श्रम को समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापक जन-जागरण अभियान चलाए जाने चाहिए। विद्यालयों, धार्मिक संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, मीडिया, उद्योग जगत और नागरिक समाज को इस दिशा में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। जिस प्रकार पर्यावरण संरक्षण और महिला अधिकारों को लेकर वैश्विक चेतना विकसित हुई है, उसी प्रकार बाल अधिकारों के लिए भी विश्वव्यापी जनमत तैयार करना होगा। कैसा विरोधाभास है कि हमारा समाज, सरकार और राजनीतिज्ञ बच्चों को देश का भविष्य मानते नहीं थकते लेकिन क्या इस उम्र के लगभग 25 से 30 करोड़ बच्चों से बाल मजदूरी के जरिए उनका बचपन और उनसे पढने का अधिकार छीनने का यह सुनियोजित षड्यंत्र नहीं लगता? मिसाल के तौर पर एक कानून बनाकर हमने बच्चों से उनका बचपन छिनने की कुचेष्टा की है। इस कानून में हमने यदि पारिवारिक कामधंधा या रोजगार है तो 4 से 14 की उम्र के बच्चों से कानूनन काम कराया जा सकता है और कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यह कैसी विडम्बना है कि जब इस उम्र के बच्चों को स्कूल में होना चाहिए, खानदानी व्यवसाय के नाम पर एक पूरी पीढ़ी को शिक्षा, खेलकूद और सामान्य बाल्य सुलभ व्यवहार से वंचित किया जा रहा है और हम अपनी पीठ थपथपाए जा रहे हैं। बच्चों को बचपन से ही आत्मनिर्भर बनाने के नाम पर हकीकत में हम उन्हें पैसा कमाकर लाने की मशीन बनाकर अंधकार में धकेल रहे हैं।

विशेष रूप से डिजिटल युग में तकनीक का उपयोग बाल श्रम उन्मूलन के लिए किया जा सकता है। प्रत्येक उद्योग और आपूर्ति श्रृंखला की पारदर्शी निगरानी, बाल श्रम शिकायतों के लिए ऑनलाइन पोर्टल, त्वरित कार्रवाई तंत्र और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी प्रणालियां विकसित की जा सकती हैं। अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनकी आपूर्ति श्रृंखला में कहीं भी बाल श्रम का उपयोग न हो। जो कंपनियां ऐसा करती पाई जाएं, उनके विरुद्ध कठोर आर्थिक और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बाल श्रम समाप्त करने का सबसे प्रभावी उपाय गुणवत्तापूर्ण और समावेशी शिक्षा है। केवल विद्यालय खोल देना पर्याप्त नहीं है; शिक्षा ऐसी हो जो बच्चों को आकर्षित करे, जीवनोपयोगी कौशल दे और उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करे। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति, पोषण, स्वास्थ्य सेवाएं और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों का विस्तार आवश्यक है। यदि परिवार की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित होगी तो बच्चों को मजदूरी के लिए भेजने की मजबूरी भी कम होगी।

देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 'रणनीति' युवा संसदीय सम्मेलन, युवाओं ने राष्ट्र निर्माण में रखे अपने विचार

पथ प्रवाह, देहरादून।

देवभूमि उत्तराखंड विश्वविद्यालय में 'रणनीति' युवा संसदीय सम्मेलन का भव्य एवं सफल आयोजन संपन्न हुआ। इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन एवं नेतृत्व रणनीति की संस्थापक एवं महासचिव उन्नति नौटियाल के मार्गदर्शन में किया गया। सम्मेलन में लगभग 300 प्रतिनिधियों तथा 40 आयोजन समिति सदस्यों ने सक्रिय सहभागिता की। उत्तराखंड सहित देश के विभिन्न राज्यों एवं अनेक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों ने इस आयोजन में भाग लेकर अपने विचार, नेतृत्व क्षमता एवं वाद-विवाद कौशल का प्रभावशाली प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के प्रथम दिवस, 8 जून को सौरभ थपलियाल एवं आर्यन देव उनियाल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण, नेतृत्व एवं नीति-निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। द्वितीय दिवस, 9 जून को राज्य मंत्री नितिन गौतम मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं प्रति-कुलपति भी उपस्थित रहे। अतिथियों ने प्रतिभागियों के उत्साह, ज्ञान एवं संवाद कौशल की सराहना करते हुए ऐसे आयोजनों को युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया।

सम्मेलन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग, अखिल भारतीय राजनीतिक दल बैठक, लोकसभा तथा महाभारत विशेष परिषद जैसी विभिन्न समितियों का गठन किया गया। इन समितियों में प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर गंभीर विचार-विमर्श, तर्कपूर्ण चर्चा तथा नीतिगत संवाद प्रस्तुत किए। इस अवसर पर रणनीति 2026 की संस्थापक एवं महासचिव सुश्री उन्नति नौटियाल के नेतृत्व की विशेष सराहना की गई, जिनकी दूरदर्शी सोच, समर्पण एवं अथक प्रयासों ने इस आयोजन को एक सशक्त मंच के रूप में स्थापित किया।

रणनीति की परिकल्पना से लेकर उसके सफल आयोजन तक उनके नेतृत्व ने युवाओं को नेतृत्व, संवाद एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का एक प्रभावी मंच प्रदान किया। कार्यक्रम के निदेशक जनरल शिवांग राजा ने आयोजन के सफल संचालन, समन्वय एवं व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से संचालित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सम्मेलन का प्रत्येक सत्र व्यवस्थित एवं प्रभावी रहा।

वहीं, मुख्य सलाहकार अभिषेक भार्गव के मार्गदर्शन एवं अनुभव ने आयोजन को एक सुदृढ़ दिशा प्रदान की तथा प्रतिभागियों और आयोजन दल को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रेरित किया। इन सभी के सामूहिक प्रयासों और नेतृत्व ने रन्नीति 2026 को एक सफल, गरिमामय एवं यादगार आयोजन बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता न होकर युवाओं के व्यक्तित्व विकास, नेतृत्व निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों के संवर्धन तथा वैचारिक जागरूकता का एक सशक्त मंच सिद्ध हुआ। सुश्री उन्नति नौटियाल के नेतृत्व में आयोजित यह सम्मेलन अत्यंत सफल, प्रेरणादायक एवं स्मरणीय रहा तथा सभी प्रतिभागियों एवं अतिथियों पर अपनी विशिष्ट छाप छोड़ने में सफल रहा।

एक नजर

चारधाम यात्रा के लिए 4920 यात्रियों ने कराया पंजीकरण

पथ प्रवाह, हरिद्वार। हरिद्वार ऋषिकुल मैदान में बनाए गए यात्री पंजीकरण केंद्र में चारधाम यात्रा के लिए 4920 यात्रियों ने अपना पंजीकरण कराया। यमुनोत्री धाम के लिए 792, गंगोत्री धाम के लिए 822, केदारनाथ धाम के लिए 1509, बद्रीनाथ धाम के लिए 1738, हेमकुंड साहिब के लिए 59 यात्रियों ने पंजीकरण कराया। इस तरह 4920 यात्रियों द्वारा चारधाम के लिए आज अपना पंजीकरण कराया गया। ऋषिकुल मैदान यात्री पंजीकरण केंद्र से अब तक कुल 4 लाख 17 हजार 1 सौ 18 यात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए अपना पंजीकरण कराया है।

हरिद्वार कुंभ मेला–2027 में स्वच्छता मिशन के लिए 115.61 करोड़ की धनराशि स्वीकृत

पथ प्रवाह, देहरादून। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की कार्यकारी समिति की 70वीं बैठक में हरिद्वार कुंभ मेला-2027 के लिए प्रस्तावित 'एकीकृत स्वच्छता, ठोस एवं तरल अपशिष्ट तथा जनस्वास्थ्य प्रबंधन योजना' के लिए 115.61 करोड की धनराशि स्वीकृत की गई है। 115.61 करोड की लागत वाली यह परियोजना पूर्णतः केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित है। परियोजना का उद्देश्य कुंभ मेले के दौरान आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल व्यवस्था सुनिश्चित करना है।

इस धनराशि से कुम्भ मेले के लिए 13,915 शौचालय, 8,065 यूरिनल तथा 2,000 स्नानगृह स्थापित किए जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए 4,840 कूड़ादान, 31.38 लाख लाइनर बैग, 491 अपशिष्ट संग्रहण वाहन, 2 ट्रैश बूम, 15 घाट सफाई मशीनें, 190 स्प्रेइंग मशीन एवं ट्रैक्टर, 55 फॉगिंग मशीनें, 30 घास काटने की मशीनें, कीटनाशक, पीपीई किट, प्राथमिक उपचार किट तथा सड़क सफाई हेतु आवश्यक उपभोग्य सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ट्रांसफर स्टेशन सुविधाओं, गैस आधारित शवदाह गृह तथा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही निगरानी एवं प्रबंधन को सुदृढ़ बनाने हेतु क्लाउड-आधारित डैशबोर्ड विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा स्वीकृत की गई धनराशि से हरिद्वार में 2027 में आयोजित होने वाले कुम्भ मेले में स्वच्छता, ठोस अपशिष्ठ तथा जन स्वास्थ्य प्रबन्धन के साथ ही निगरानी एवं प्रबन्धन को सुदृढ बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री का भी आभार व्यक्त किया।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का ज़ोर

पथ प्रवाह, हरिद्वार। नोडल अधिकारी स्वच्छता चन्द्रकांत मणि त्रिपाठी ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रुड़की ने जिलाधिकारी, मयूर दीक्षित के निर्देशों व सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में 'ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026' के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विभागवार निर्देश जारी करने का आग्रह किया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित सिविल अपील के अनुपालन में आदेश जारी किया गया है। इन आदेशों के तहत ठोस अपशिष्टों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, रुड़की ने जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 26 मई 2026 के अनुपालन में 19 सॉलिड वेस्ट डंप साइट्स का निरीक्षण किया है। इस निरीक्षण का विस्तृत विवरण जियो-टैग फोटोग्राफ्स सहित संलग्न किया गया है। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय कार्यालय ने ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम 2026 के अनुपालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दो महत्वपूर्ण पोस्टर तैयार किए हैं। एक पोस्टर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के बारे में जानकारी देता है, जबकि दूसरा प्रतिबंधित एकल-उपयोग प्लास्टिक (Banned Single Use Plastic Items) वस्तुओं के संबंध में जागरूकता फैलाता है। इन पोस्टरों का उपयोग जन-जागरूकता अभियान के लिए किया जाएगा और इनकी प्रतियां सभी स्थानीय निकायों को भी उपलब्ध कराई जाएंगी। बोर्ड ने इस पत्र के माध्यम से विभिन्न स्थानीय निकायों और संबंधित अधिकारियों को ठोस अपशिष्ट डंप साइटों के निस्तारण हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जिन निकायों को प्रतिलिपि भेजी गई है, उनमें नगर निगम रुड़की, नगर निगम हरिद्वार, नगर पालिका परिषद मंगलौर, और विभिन्न नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी शामिल हैं। जिला पंचायती राज अधिकारी को भी निर्देश दिया गया है कि वे संबंधित ग्राम पंचायत अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देशित करें।

गंगदासपुर क्षेत्र का जिलाधिकारी ने किया स्थलीय निरीक्षण, मानसून से पहले सभी तैयारी पूरी करने के निर्देश

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

आगामी मानसून को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तहसील लक्सर के बाढ़ एवं जल भराव के प्रति अत्यधिक संवेदनशील गंगदासपुर क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कर बाढ़ सुरक्षा एवं जलभराव की समस्या से निपटने हेतु की जा रही तैयारियों एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मानसून से पूर्व सभी आवश्यक कार्यों को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान गंगा दासपुर क्षेत्र में बाढ़ एवं जल भराव की समस्या के स्थायी समाधान के लिए गत वर्ष मुख्यमंत्री द्वारा गंगदासपुर क्षेत्र का भ्रमण के दौरान दिए गए निर्देशों का उल्लेख करते हुए उनके अनुपालन के संबंध में संबंधित विभागों के अधिकारियों से विस्तार से जानकारी प्राप्त की। जिलाधिकारी ने इस संबंध में मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रम में वर्तमान में संचालित कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को तेजी से संचालित करने के सख्त निर्देश दिए।

उन्होंने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ ही उपजिलाधिकारी लक्सर अनिल कुमार शुक्ला को निर्देशित किया कि क्षेत्र में बाढ़ से बचाव एवं जल निकासी से संबंधित सभी व्यवस्थाएं मानसून प्रारंभ होने से पूर्व पूर्ण कर ली जाएं, ताकि ग्रामीणों को किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

स्थलीय निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने ग्रामीणों से संवाद कर मानसून के समय गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं की जानकारी प्राप्त की। साथ ही, गांव में प्रस्तावित विकास एवं बाढ़ सुरक्षा कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए ग्रामीणों को जल निकासी संबंधी योजनाओं की जानकारी भी दी।

उन्होंने गंगदासपुर में गेट निर्माण, गंगदासपुर से पंडितपुर तक नाले के चैनलाइजेशन, नालों की नियमित साफ-सफाई तथा क्षेत्र के सभी छोटे-बड़े जल निकासी मार्गों को सुचारु एवं दुरुस्त बनाए रखने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा का जलस्तर बढ़ने की स्थिति में क्षेत्र में जलभराव की समस्या गंभीर रूप धारण कर सकती है। ऐसे में गेट निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र प्रारंभ किया जाना आवश्यक है।

उन्होंने संबंधित कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि सभी कार्य निर्धारित समयावधि में गुणवत्ता के साथ पूर्ण किए जाएं, जिससे मानसून के दौरान क्षेत्रवासियों को राहत मिल सके तथा किसी भी संभावित बाढ़ अथवा जलभराव की स्थिति का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके।

निरीक्षण के दौरान उपजिलाधिकारी लक्सर अनिल कुमार शुक्ला, अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग सोनू त्यागी, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग ओम जी गुप्ता, सहायक अभियंता विजय सिंह सहित संबंधित अधिकारी एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

हैलो.... मैं थानाध्यक्ष सिडकुल बोल रहा हूं, थानेदारों ने बजायी शिकायतकर्ताओं के फोन की घंटी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का एसएसपी नवनीत सिंह के निर्देश पर फीड बैक लिया जा रहा है। सभी थानाध्यक्ष और प्रभारियों से कहा गया है कि वह शिकायतकर्ता से फीडबैक जरूर लें, यदि वह शिकायत के समाधान से संतुष्ट नहीं है तो उचित कार्रवाई कर उसका समाधान किया जाए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार नवनीत सिंह के निर्देशानुसार सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर फीडबैक प्राप्त करने हेतु समस्त थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में सिडकुल थानाध्यक्ष अजय शाह ने भी फोन पर शिकायतकर्ता से फीड बैक लिया। इस दौरान शिकायतकर्ताओं से उनकी शिकायतों के निस्तारण के संबंध में थाना प्रभारी द्वारा जानकारी ली गई तथा पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के प्रति उनकी संतुष्टि का आकलन किया गया। साथ ही भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर तत्काल पुलिस से संपर्क करने की अपील की गई।

हरिद्वार पुलिस जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित, प्रभावी एवं पारदर्शी निस्तारण के लिए प्रतिबद्ध है तथा पुलिस विभाग से संबंधित समस्या की जवाबदेह पुलिसिंग के उद्देश्य से लगातार कार्य कर रही है।.

होटल एसोसिएशन यमुनावैली ने एसपी कमलेश उपाध्याय का किया सम्मान

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

चारधाम यात्रा 2026 के सफल, सुरक्षित एवं सुगम संचालन को लेकर होटल एसोसिएशन यमुनावैली के पदाधिकारियों ने गुरुवार को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय से शिष्टाचार भेंट कर उत्तरकाशी पुलिस के कार्यों की सराहना की। प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा मार्ग पर पुलिस द्वारा की गई प्रभावी यातायात व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन, खोया-पाया सहायता, श्रद्धालुओं की सुरक्षा तथा 24म7 मुस्तैद ड्यूटी की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष सोबन सिंह राणा ने कहा कि इस वर्ष यमुनोत्री धाम मार्ग पर पुलिस का व्यवहार अत्यंत संवेदनशील एवं पेशेवर रहा। ट्रैफिक जाम की स्थिति नगण्य रही, पार्किंग व्यवस्था बेहतर

दिखी तथा होटल व्यवसायियों को भी हरसंभव सहयोग मिला, जिससे श्रद्धालुओं का यात्रा अनुभव सुखद रहा और स्थानीय व्यापार को भी लाभ मिला। यात्रा के दौरान नशे तथा अवैध शराब की तस्करी पर भी अंकुश देखने को मिला है। पुलिस द्वारा कई नशा तस्करों को गिरफ्तार कर हृष्ठक्क् ष्ह्ल के केस दर्ज किये गये हैं। इस अवसर पर होटल एसोसिएशन द्वारा पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी को प्रशस्ति पत्र भेंट कर सम्मानित किया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार के समन्वय की अपेक्षा व्यक्त की। एसोसिएशन एवं यात्रा कारोबारियों ने बताया कि उत्तरकाशी पुलिस की चुस्त-दुरुस्त व्यवस्थाओं के परिणामस्वरूप चारधाम यात्रा के अब तक के 59 दिनों में लगभग 11.30 लाख श्रद्धालुओं ने श्री गंगोत्री एवं श्री यमुनोत्री धाम के सुरक्षित एवं निर्बाध दर्शन कर सुखद यात्रा का अनुभव प्राप्त किया है। पुलिस अधीक्षक कमलेश उपाध्याय ने होटल एसोसिएशन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तरकाशी पुलिस का लक्ष्य 'सुरक्षित यात्रा - सुखद यात्रा' है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जनता, व्यापारियों, यात्रा कारोबारियों एवं श्रद्धालुओं के सहयोग से 'सुविधा, सुरक्षा एवं सम्मान' के संकल्प के साथ यात्रा व्यवस्थाओं को आगे भी और अधिक बेहतर बनाया जाएगा। इस दौरान एसपी उत्तरकाशी द्वारा प्रबुद्ध जनों से यात्रा व पुलिस व्यवस्थाओं को ओर अधिक प्रभावी व सुदृढ़ करने हेतु सुझाव भी लिए गये।

इस अवसर पर होटल एसोसिएशन यमुनावैली के अध्यक्ष सोबन सिंह राणा, श्री यमुनोत्री धाम के रावल ज्योति प्रसाद उनियाल, पूर्व प्रधान चैन सिंह रावत, उपाध्यक्ष अनिल सिंह चौहान, धनश्याम नौटियाल, दिपिन राणा, विनोद डिमरी, राजदीप रौतेला, बलदेव परमार, अभिषेक सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

एक नजर

यूकेएसएसएससी परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा, निष्पक्ष संचालन के दिए निर्देश

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 14 जून को आयोजित होने वाली विभिन्न विभागों के स्नातक स्तरीय पदों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा के सफल एवं निष्पक्ष संचालन को लेकर जिलाधिकारी अंशुल सिंह ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक नवीन कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। गुरुवार को आयोजित बैठक में परीक्षा से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने परीक्षा केन्द्रों पर सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, विद्युत आपूर्ति और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। जिलाधिकारी ने परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करने तथा परीक्षा केन्द्रों की व्यवस्थाओं का पूर्व सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केन्द्रों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों और जैमर की कार्यशीलता का पूर्व परीक्षण कर लिया जाए तथा परीक्षा अवधि के दौरान उनकी सतत निगरानी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा के दौरान पूरी सतर्कता और जिम्मेदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए। साथ ही किसी भी समस्या की स्थिति में त्वरित समन्वय स्थापित कर उसका समाधान सुनिश्चित करने को कहा। दूरस्थ क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्र, नगर आयुक्त सीमा विश्वकर्मा सहित परीक्षा से जुड़े विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

अल्मोड़ा पुलिस का महिला सुरक्षा व साइबर जागरूकता अभियान

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। महिला सुरक्षा और साइबर अपराधों से बचाव को लेकर अल्मोड़ा पुलिस ने विशेष जागरूकता अभियान चलाया। विक्टर मोहन जोशी राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, एनटीडी में छात्राओं को साइबर फ्रॉड, पॉक्सो एक्ट और महिला अपराधों की जानकारी दी गई। एसएसपी चंद्रशेखर घोडके के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत एएसपी हरबंस सिंह के मार्गदर्शन और सीओ बलवंत सिंह रावत के पर्यवेक्षण में प्रभारी महिला कोतवाली जानकी भंडारी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। अपर उपनिरीक्षक बीना दोसाद व महिला कांस्टेबल तुलसी गोस्वामी ने छात्राओं को सोशल मीडिया के दुष्परिणाम, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसी ठगी से बचाव के तरीके बताए। टीम ने कहा कि स्कूल आते-जाते या घर पर कोई समस्या हो तो तुरंत 112 और साइबर अपराध पर 1930 पर कॉल करें। शिक्षिकाओं से भी समय-समय पर छात्राओं को जागरूक करने को कहा गया। पुलिस ने चेताया कि अगर कोई कॉल पर खुद को सीबीआई, ईडी या पुलिस अफसर बताकर धमकाए और पैसे मांगे तो घबराएं नहीं, तुरंत पुलिस को सूचना दें।

श्री गंगोत्री धाम में एसडीआरएफ के जवान ने बचायी 77 वर्षीय श्रद्धालु की जान

पथ प्रवाह, उत्तरकाशी।

छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जनपद से चारधाम यात्रा पर आए 77 वर्षीय बुजुर्ग श्रद्धालु चंद्रहास सिंह श्री गंगोत्री धाम में स्नान के दौरान अचानक पैर फिसलने से भागीरथी नदी की मुख्य धारा के तेज बहाव में बह गए।

घटना के समय ड्यूटी पर तैनात एसडीआरएफ जवान नवीन पोखरिया ने अदम्य साहस, तत्परता एवं सूझबूझ का परिचय देते हुए बिना समय गंवाए लाइव रिंग तथा पुलिस द्वारा पूर्व में नदी के आर-पार लगाए गए फंदायुक्त सुरक्षा रस्सियों की सहायता से नदी में छलांग लगाई और श्रद्धालु को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। एसडीआरएफ जवान की त्वरित एवं साहसिक कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया तथा श्रद्धालु की जान बच गई। इस मानवीय एवं वीरतापूर्ण कार्य को देखकर मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं एवं तीर्थपुरोहितों ने उत्तराखण्ड पुलिस एवं एसडीआरएफ की भूरि-भूरि प्रशंसा

करते हुए जवानों के सम्मान में जयघोष किया गया।

श्रद्धालुओं एवं तीर्थयात्रियों से अनुरोध है कि श्री गंगोत्री धाम में भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए सभी श्रद्धालु अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दें तथा गंगा घाटों के किनारों एवं तेज बहाव वाले क्षेत्रों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। पुलिस-प्रशासन द्वारा जारी सुरक्षा निर्देशों का पालन करें नदी में उतरकर स्नान करने का प्रयास न करें। स्नान हेतु लोटे अथवा मग के माध्यम से गंगाजल लेकर स्नान करें, जिससे किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। आपकी सतर्कता और सहयोग ही आपकी सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करेगा।

अवैध प्लॉटिंग और रियल एस्टेट अनियमितताओं पर कसेगा शिकंजा

पथ प्रवाह, देहरादून।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर उत्तराखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (रेरा) में व्यापक सुधारों की तैयारी शुरू हो गई है। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में रेरा की कार्यप्रणाली, परियोजनाओं की निगरानी, शिकायत निस्तारण, बिल्डरों के पंजीकरण तथा अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण को लेकर कई महत्वपूर्ण सुझाव और निर्देश दिए गए। सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने निर्देश दिए कि देश के विभिन्न राज्यों जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, दिल्ली, असम और हिमाचल प्रदेश में लागू रेरा व्यवस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन कर उत्तराखंड के लिए सर्वोत्तम व्यवस्थाएं अपनाई जाएं। इसके लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य में लागू किए जाने वाले सुधारों का खाका तैयार किया जाएगा।

सचिव आवास एवं राज्य सम्पत्ति डॉ. आर. राजेश कुमार ने समीक्षा बैठक में रेरा के ऑनलाइन पोर्टल को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (Ease of Doing Business) से एकीकृत करने का सुझाव भी दिया गया, जिससे परियोजना पंजीकरण और अनुमोदन प्रक्रियाएं अधिक सरल, पारदर्शी और समयबद्ध हो सकें।

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने यह भी प्रस्तावित किया गया कि रेरा पंजीकरण के बाद जारी प्रमाणपत्र में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाए कि स्वीकृत मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने से पहले संबंधित परियोजना के कम से कम दो-तिहाई आवंटियों की सहमति लेना अनिवार्य होगा। इससे फ्लैट और प्लॉट खरीदारों के हितों की बेहतर सुरक्षा

सुनिश्चित हो सकेगी। इसके अलावा राज्य में बिल्डर और प्रमोटर पंजीकरण व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने पर भी चर्चा हुई। प्रमोटरों द्वारा पूर्व में विकसित की गई परियोजनाओं का पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया गया, जिससे खरीदारों को डेवलपर के ट्रैक रिकॉर्ड की जानकारी मिल सके।

अवैध प्लॉटिंग पर रेरा की नजर

अवैध प्लॉटिंग और बिना स्वीकृति के निर्माण गतिविधियों पर भी गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सचिव आवास ने कहा कि विभिन्न विकास प्राधिकरणों से ऐसे मामलों की सूचनाएं लगातार सामने आ रही हैं। इस पर रेरा स्तर से किस प्रकार प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, इसके लिए विस्तृत अध्ययन करने के निर्देश दिए गए। साथ ही यह भी तय किया गया कि जिन निर्माणों के विरुद्ध विकास प्राधिकरणों द्वारा सीलिंग, ध्वस्तीकरण या अन्य कार्रवाई की जाती है, उनकी सूचना रेरा को भी उपलब्ध कराई जाए। इससे खरीदारों को संभावित जोखिम वाली परियोजनाओं की जानकारी मिल सकेगी और रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी।

परियोजनाओं की स्वीकृति के लिए स्पष्ट टाइमलाइन तय करने पर भी जोर दिया गया ताकि निवेशकों और खरीदारों को अनावश्यक देरी का सामना न करना पड़े।

रेरा के वर्तमान प्रभारी अध्यक्ष नरेश मठपाल ने बैठक में बताया कि 500 वर्ग मीटर से अधिक भूखंड क्षेत्रफल अथवा आठ से अधिक निर्मित इकाइयों वाली सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए विज्ञापन, बुकिंग, आवंटन तथा क्रय-विक्रय से पूर्व रेरा में पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि परियोजना और एजेंट पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु 30 कार्य दिवस की समय-सीमा निर्धारित की गई है।

रेरा की उपलब्धियों पर जानकारी देते हुए वर्तमान प्रभारी अध्यक्ष नरेश मठपाल ने बताया गया कि वर्ष 2017 में गठन के बाद से अब तक राज्य में 689 रियल एस्टेट परियोजनाएं पंजीकृत हो चुकी हैं। हिमालयी राज्यों में परियोजना पंजीकरण के मामले में उत्तराखंड दूसरे स्थान पर है।

एक नजर

लंबगांव हत्याकांड : 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस जांच तेज

पथ प्रवाह, नई टिहरी। टिहरी जनपद के चर्चित लंबगांव हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। मामले में दो और आरोपियों–सचिन पंवार और सुमित प्रसाद–को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक, दोनों की संलिप्तता जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर सामने आई। इससे पहले भी इस हत्याकांड में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका था। ताजा कार्रवाई के बाद अब कुल चार आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) श्वेता चौबे ने बताया कि मामले की निष्पक्ष और गहन विवेचना जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस हत्याकांड में शामिल किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अब मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है, ताकि घटना के पीछे की पूरी साजिश और कारणों का खुलासा किया जा सके। इस घटना के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है।

हरिद्वार में होटल ढाबों पर खाद्य विभाग का छापा, खुला पनीर नष्ट कराया

पथ प्रवाह, हरिद्वार। सहायक आयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी सच्चिदानंद जोशी के नेतृत्व

में खाद्य सुरक्षा विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग और बाट व माप नियंत्रण की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया। भूपतवाला और दुधाधारी चौक क्षेत्र में स्थित होटल, ढाबा एवं रेस्टोरेन्ट का निरीक्षण किया गया। जिसमें 6 ढाबों के संचालक को साफ सफाई न होने एवं लाइसेन्स में प्रतिष्ठान का पता सही न होंने पर नोटिस जारी किया गया। साथ ही तीन नमूना मसाले के लेकर जांच के लिए खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। एक प्रतिष्ठान पर लगभग 1.5 किलो खुला पनीर नष्ट कराया गया। सभी खाद्य कारोबारियों को रसोई और फ्रिज की साफ-सफाई व्यवस्थित करने के लिए निर्देश दिये गए। बाट माप नियंत्रण विभाग द्वारा एक प्रतिष्ठान का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर बिक्री करने पर चालान किया गया। खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा सभी प्रतिष्ठानों को रेट लिष्ट चस्पा करने एवं घरेलू सिलेण्डर का व्यवसायिक प्रयोग नहीं करने के निर्देश दिये गए। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी पवन कुमार एवं क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी देवचंद, पूर्ति निरीक्षक मुकुल शर्मा एवं वरिष्ट निरीक्षक विधिक माप विज्ञान प्रदीप बिजलवाल शामिल रहे।

भाजपा और रानीपुर विधायक की लोकप्रियता से बौखलाई कांग्रेस : अतुल वशिष्ठ

पथ प्रवाह, हरिद्वार। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा रानीपुर विधायक आदेश चौहान के कैंप कार्यालय पर किए गए प्रदर्शन को भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से खारिज किया है। भाजपा ने इसे कांग्रेस की घोर हताशा और राजनीतिक बौखलाहट का परिणाम बताया है। इस अवसर पर जारी अपने बयान में भाजपा नेता सांसद प्रतिनिधि अतुल वशिष्ठ ने कहा कि कांग्रेस आज धरातल पर जनता के बीच पूरी तरह से शून्य हो चुकी है। रानीपुर के लोकप्रिय विधायक आदेश चौहान द्वारा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों और जनता के साथ उनके सीधे जुड़ाव ने विपक्ष की बची कुची जमीन खिसका दी है। भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेता केवल चुनाव के समय 'बरसाती मेंढ़कों' की भांति बाहर निकलते हैं और सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ड्रामा करते हैं। जनता इनके खोखले दावों की सच्चाई भली-भांति जानती है और पहले भी इन्हें नकार चुकी है। वशिष्ठ ने स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी की केन्द्र व राज्य सरकार और रानीपुर विधायक की जन-कल्याणकारी नीतियों और उनकी बेदाग कार्यशैली से आमजन में भारी उत्साह है। कांग्रेस के इस तरह के ओछे हथकंडों और प्रदर्शनों से भाजपा की लोकप्रियता और विकास कार्यों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। रानीपुर की जनता विकास के साथ है और आने वाले चुनावों में भी पूर्व की भांति भाजपा को अपना पूर्ण आशीर्वाद देगी।

लाखों रूपए की धोखाधड़ी का आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। फर्जी पर्चेज आर्डर लगाकर लाखों रूपए की धोखाधड़ी करने के आरोपी को थाना पथरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बीती 23 मई को ज्वालापुर निवासी चंदन कौचर थाना पथरी पुलिस को शिकायत देकर कम्पनी के फर्जी पर्चेज आर्डर जारी कर धोखाधडी से वादी की फैक्टरी को आर्थिक हानि पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने आरोपित कुलदीप कुमार पाण्डेय पुत्र संजीव कुमार निवासी गली न.6 कमलानगर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस टीम में एसआई विपिन कुमार, कांस्टेबल दीपक चौधरी व जयपाल चौहान शामिल रहे।

भाकियू (रोड) की पंचायत में किसानों की समस्याओं पर मंथन, बकाया भुगतान न होने पर सीएम आवास घेराव की चेतावनी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

किसानों की विभिन्न समस्याओं के निस्तारण को लेकर भारतीय किसान यूनियन (रोड) की ज्वालापुर तहसील में आयोजित मासिक पंचायत में किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। पंचायत में गन्ना किसानों के बकाया भुगतान, स्मार्ट मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया संगठन ने मांगें पूरी न होने पर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी। वहीं पंचायत की सूचना मिलने के बावजूद हरिद्वार एसडीएम योगेश मेहरा के न पहुंचने पर भाकियू कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जतायी।

किसानों की चेतावनी के बाद एसडीएम हरिद्वार किसानों के बीच पहुंचे और किसानों की समस्याओं को सुना। कुछ समस्याओं का पंचायत में मौजूद अन्य विभागों के अधिकारियों से समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। सरदार बिशन सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किसान पंचायत का संचालन प्रदेश महासचिव प्रदीप त्यागी ने किया। इस दौरान भाकियू रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी पदम सिंह रोड ने संगठन को धार देते बताया कि अनुशासन बनाए रखने के लिए ग्यारह सदस्यों की एक समिति का गठन करने की घोषणा करते हुए कहा कि संगठन में अनुशासन सर्वोपरि है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का किसान आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर एक सप्ताह के भीतर किसानों का बकाया भुगतान नहीं कराया गया तो भाकियू कार्यकर्ता देहरादून के लिए कूच करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष संजीव कुशवाहा ने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया का हर हाल में विरोध किया जाएगा। वहीं प्रदेश महासचिव विकास शर्मा ने कहा कि किसानों के हितों की अनदेखी को किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पंचायत में वक्ताओं ने कहा कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए संगठन लगातार संघर्ष करता रहेगा।इस अवसर पर प्रवीण कुशवाहा, सुंदरम शर्मा,कारी शहजाद, इरशाद प्रधान, वारिस अली, जावेद अली, जव्वाद, रियासत,अनुज त्यागी,आसिफ अली, टीटू, मतलूब, मोनू मलिक, मोमिन, परवेज और गोपाल उर्फ मुन्नू सहित बड़ी संख्या में किसान और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे।

जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के नए प्रशासक ने संभाला कार्यभार, 15 दिन की योजना रखी सामने

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, हरिद्वार में एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन के तहत आनंद ए.डी. शुक्ल, अपर निबंधक सहकारी समितियां, उत्तराखंड ने बैंक के प्रशासक पद का कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार संभालते ही उन्होंने बैंक की प्रगति एवं कार्यप्रणाली को गति देने के उद्देश्य से सभी शाखा प्रबंधकों की समीक्षा बैठक आयोजित की तथा आगामी 15 दिनों के लिए एक महत्वाकांक्षी पंचसूत्रीय कार्ययोजना घोषित की।

बैठक में प्रशासक श्री शुक्ल ने जनपद की शेष दो प्राथमिक कृषि ऋण समितियों–पनियाला एवं पथरी–का कंप्यूटरीकरण पूर्ण कर उन्हें ई-पैक्स के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जनपद मुख्यालय पर बैंक के नाम से आवंटित भूमि पर भवन निर्माण हेतु सभी आवश्यक औपचारिकताओं को शीघ्र पूर्ण करने पर बल दिया गया।

उन्होंने बैंक में 3 से 5 वर्षों से एक ही शाखा अथवा पटल पर कार्यरत पात्र कर्मचारियों की स्थानांतरण सूची तैयार करने के निर्देश भी दिए, जिससे प्रशासनिक दक्षता एवं पारदर्शिता को बढ़ावा मिल सके। इसके अलावा 10 लाख रुपये से अधिक के सभी एनपीए खातों में सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा ऋण वसूली एजेंसियों के कार्यों की समीक्षा कर आवश्यकतानुसार नई एजेंसियों की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा बैठक के दौरान शाखावार निक्षेप वृद्धि, विविधीकृत ऋण वितरण एवं बैंक के व्यवसाय विस्तार की संभावनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। प्रशासक ने सभी शाखा प्रबंधकों को ऋण वितरण में वृद्धि कर अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में जिला विकास प्रबंधक, नाबार्ड अखिलेश डबराल ने भी बैंक अधिकारियों को ग्रामीण वित्तीय समावेशन एवं व्यवसाय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देते हुए बैंकिंग गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। अपने संबोधन में आनंद ए.डी. शुक्ल ने कहा कि बैंक की सतत प्रगति, वित्तीय सुदृढ़ता और ग्राहकों के विश्वास को बनाए रखने के लिए स्पष्ट, समयबद्ध एवं परिणामोन्मुख कार्ययोजना आवश्यक है। उन्होंने एनपीए वसूली में तेजी लाने, ग्राहकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा बैंक के व्यवसायिक विस्तार के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों से समन्वित प्रयास करने का आह्वान किया। बैठक में बैंक के सचिव/महाप्रबंधक सौ सिंह, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड अखिलेश डबराल, उप महाप्रबंधक चरण सिंह सहित बैंक के वरिष्ठ अधिकारी एवं सभी शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे।

शिवालिकनगर चौक पर जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओ ने किया प्रदर्शन

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

युवा कांग्रेस के रानीपुर विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष सौरभ सैनी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिवालिक नगर चौक पर जनसमस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद कार्यकर्ताओं ने विधायक के कैंप कार्यालय का घेराव किया।

इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बालेश्वर सिंह और राजबीर चौहान ने कहा कि रानीपुर विधानसभा की जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रही है। लेकिन विधायक क्षेत्र की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं हैं। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रविश भटीजा और संजय सैनी ने कहा कि रानीपुर विधानसभा का अधिकांश हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र है, जहां बरसात के समय कई स्थानों पर जलभराव की गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। पिछले 15 वर्षों से विकास कार्य ठप पड़े हैं और जनता को मूलभूत सुविधाओं का अभाव झेलना पड़ रहा है। मनोज धनगर और मनोज जाटव ने आरोप लगाया कि सरकार जनता के विकास कार्यों से ध्यान हटाकर केवल धार्मिक और साम्प्रदायिक मुद्दों पर राजनीति कर रही है तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। यशवंत सिंह सैनी, मोहन सिंह राणा, कैलाश प्रधान ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय क्षेत्र में अनेक विकास कार्य हुए थे। लेकिन पिछले 15 वर्षों में विकास की गति रुक गई है। क्षेत्र में नए अस्पताल और स्कूल नहीं खोले गए हैं तथा मेडिकल कालेज की ओपीडी सेवाएं भी प्रभावित हैं, जिससे आम जनता परेशान है। सुरेंद्र ठाकुर ने कहा कि जनता इस बार बदलाव के मूड में है और अपने वोट के अधिकार से बीजेपी को आईना दिखाने का काम जनता करेगी। कांग्रेस नेताओं ने क्षेत्र की मूलभूत समस्याओं के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि जनहित के मुद्दों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। इस दौरान रवीश भटीजा, मनोज जाटव, यशवंत सैनी, मोहन सिंह राणा, सुरेंद्र ठाकुर, समर्थ अग्रवाल, कैलाश प्रधान, सतीश दुबे, ओबीसी महानगर अध्यक्ष राजेंद्र श्रीवास्तव, डा.मेहरबान, जितेंद्र चौधरी, रियाजुल अली, समीर अंसारी, राव मोइन, पवन पाल, प्रवीण धनगर, सत्यपाल शास्त्री सहित भारी संख्या पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल रहे।

एक नजर

बुजुर्ग ने लगाया पुत्र व पुत्रवधू पर घर से निकालने का आरोप

पथ प्रवाह, हरिद्वार। बुजुर्ग ने पुत्र व पुत्रवधू पर मारपीट कर घर से निकालने के आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। प्रैस क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए बुजुर्ग ने कहा कि न्यायालय से राहत के बावजूद पुलिस प्रशासन उन्हें उनके मकान में आज तक कब्जा नहीं दिला पाया है। चोपड़ा भवन रानी गली भूपतवाला निवासी 70 वर्षीय राजबीर पुरी पुत्र भगवानपुरी ने बताया कि उनके पुत्र और पुत्रवधू ने उनसे दुर्व्यवहार करते हुए उन्हें उनके मकान से निकाल दिया है। जिसके बाद से वह इधर उधर भटक रहे हैं। राजबीर पुरी ने बताया कि उनके मकान में ही उनकी दुकान भी है। जिसका संचालन वह स्वयं करते थे। बीमार होने पर षड़यंत्र के तहत उन्हें मकान और दुकान से बाहर कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने एसडीएम कोर्ट में वाद दायर किया। जिसमें 23 सितम्बर 2025 को उनके हक में फैसला आने के बावजूद उन्हें मकान और दुकान पर कब्जा नहीं दिलाया गया। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले का अनुपालन करते हुए पुलिस और प्रशासन उन्हें मकान और दुकान पर कब्जा दिलाए।

पुलिस जवान की सूझबूझ से यात्री को खोया बैग वापस मिला

पथ प्रवाह, हरिद्वार। श्यामपुर पुलिस के जवान की सूझबूझ और डयूटी के प्रति कर्तव्यनिष्ठा के चलते आटो में छूटा यात्री का बैग वापस मिल गया। जानकारी के अनुसार बांदा उत्तर प्रदेश से मां चंडी देवी दर्शन के लिए आए श्रद्धालु रजनीश कुमार का बैग गलती से ऑटो में छूट गया। बैग में उनका कीमती सामान रखा था। रजनीश कुमार ने चंडीघाट चौकी पहुंचकर पुलिस को सूचना दी। चैकी में तैनात कांस्टेबल राजबीर सिंह ने सीसीटीवी की मदद से आटो चालक के बारे जानकारी निकाली और उसे चौकी बुलाकर सामान सहित बैग रजनीश कुमार को वापस वापस दिलाया। बैग और सामान वापस मिलने पर रजनीश कुमार और उसके साथियों ने पुलिस का आभार जताया।

जान से मारने की नीयत से गोली चलाने का आरोपी गिरफ्तार

पथ प्रवाह, हरिद्वार। जान से मारने की नीयत से गोली चलाने के आरोपी को लक्सर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपित को कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक बीती 10 जून को लकसरी गांव निवासी जावेद ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर समीर उर्फ आसु समेत 5 व्यक्तियों को नामजद करते हुए घर में घुसकर मारपीट करने और जान से मारने की नीयत से फायर करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद आरोपितों की धरपकड़ की कार्रवाई करते हुए आरोपी समीर उर्फ आशु को तमंचे व कारतूस समेत दबोच लिया। अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। पूछताछ में सामने आया कि 9 जून को आरोपी समीर की मां और बहन जावेद के मौहल्ले में गयी थी। जहां जावेद की मां ने समीर की मां और बहन के साथ गाली गलौच और लड़ाई झगड़ा किया था। जिस पर समीर अपने भाई साहिल के साथ जावेद के घर के बाहर पहुंचा और ऊपर फायर कर दिया। पुलिस टीम में एसएसआई नितिन चौहान, एसआई विपिन कुमार, हेडकांस्टेबल शमशेर खान, होमगार्ड प्रदीप कुमार शामिल रहे।

कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, अल्मोड़ा में विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत दो दिवसीय कुमाऊं मंडल के दौरे पर हैं। इस दौरान वे अल्मोड़ा जनपद में उच्च शिक्षा विभाग की कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करेंगे। साथ ही शैक्षणिक व सहकारी संस्थानों का औचक निरीक्षण भी करेंगे। डॉ. रावत 12 जून को राजकीय महाविद्यालय तल्ला-सल्ट में नवनिर्मित अकादमिक भवन और राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रानीखेत में वाणिज्य संकाय के नव निर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद केंद्र सरकार के 'विकास, विश्वास व जनकल्याण के 12 वर्ष' पूरे होने पर प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे।अल्मोड़ा जनपद के प्रभारी मंत्री डॉ. रावत दौरे में विभिन्न महाविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों और सहकारी समितियों का औचक निरीक्षण करेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 12 साल पूरे कर लिए हैं।

किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा: ऋषिपाल अंबावत

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

अलकनंदा मैदान पर आयोजित भारतीय किसान यूनियन अंबावत के राष्ट्रीय अधिवेशन एवं चिंतन शिविर के दूसरे दिन किसानों को संबोधित करते हुए यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है और किसान ही देश का असली राजा है।

किसान कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है। महंगी खाद और बिजली के चलते खेती करना मुश्किल हो गया है। समस्याओं के समाधान के लिए किसान लगातार आवाज उठा रहे हैं। लेकिन सरकार पर कोई असर नहीं हो रहा है। चौधरी ऋषिपाल अंबावता ने कहा कि सरकार गैस और तेल के दाम लगातार बढ़ा रही है। लेकिन किसानों को फसलों पर एमएसपी देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि भाकियू अंबावता का किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देश का किसान ही हमारी पार्टी और नेता है। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल कदम नहीं उठाए तो दिल्ली में जंतर मंतर पर आंदोलन किया जाएगा। सरकार एमएसपी पर फसल खरीद की गारंटी देकर अपने वादे को पूरा करे। अंबावता ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चैधरी चरण सिंह और किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत उनके आदर्श हैं। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह और स्वर्गीय महेंद्र सिंह टिकैत के दिखाए मार्ग पर चलते हुए किसानों के हितों के लिए संघर्ष निरंतर जारी है। उन्होंने कहा कि यदि किसानों की सुध नहीं ली गयी तो 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा का विरोध किया जाएगा और किसानों के हितों के लिए भारतीय किसान यूनियन अंबावता किसी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटेगी। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चौधरी और अन्य प्रदेशों से आए किसान नेताओं ने भी अधिवेशन को संबोधित किया। अधिवेश का संचालन राष्ट्रीय महासचिव रामपाल सिंह अंबावता ने किया। प्रवीन अंबावता, उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी सचिन चैधरी, प्रदेश अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, युवा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र प्रधान, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष दिलबाग हुड्डा, हरियाण प्रभारी चुहड़ सिंह रावत, रमन पंवार, नसीर खान, परशुराम प्रधान, तौफीक, रामानुज सिंह, सुभाष चौधरी, रविंद्र प्रधान, धीरेंद्र रावत, अमृत सिंह, अशोक मिश्रा, महीपाल सिंह, नीलकमल पांडे आदि पदाधिकारियों सहित हजारों की संख्या में किसान मौजूद रहे।

एसआईआर की प्रगति जानने गंगदासपुर गाँव पहुंचे जिलाधिकारी

पथ प्रवाह, हरिद्वार।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने गंगदासपुर क्षेत्र का भ्रमण कर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की प्रगति का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य से संबंधित व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) से जानकारी प्राप्त की।

निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने बीएलओ को निर्देशित किया कि एसआईआर अभियान के अंतर्गत निर्धारित समयावधि में सभी पात्र मतदाताओं का सत्यापन एवं आवश्यक अभिलेखों का संकलन में तेजी लायी जाए। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता एवं पारदर्शिता लोकतांत्रिक प्रक्रिया की मजबूती के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए।

जिलाधिकारी ने संबंधित बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को घर-घर जाकर सत्यापन कार्य में तेजी लाने तथा छूटे हुए पात्र मतदाताओं को सूची में शामिल करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए।

उत्तरायण अस्पताल के निशुल्क हेल्थ कैंप में 140 लोगों ने कराया स्वास्थ्य परीक्षण

पथ प्रवाह, अल्मोड़ा

?उत्तरायण फाउंडेशन और नेशनल हार्ट इंस्टिट्यूट की ओर से आम जनमानस को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक निशुल्क हेल्थ कैंप (स्वास्थ्य शिविर) का आयोजन किया गया। उत्तरायण अस्पताल के तत्वावधान में लगाए गए इस शिविर में क्षेत्र के 140 लोगों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और विशेषज्ञों से स्वास्थ्य संबंधी उचित परामर्श लिया।

?इस स्वास्थ्य शिविर में कई जाने-माने विशेषज्ञ डॉक्टरों ने मरीजों की जांच की। शिविर में मुख्य रूप से वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. ओपी यादव, वरिष्ठ जनरल सर्जन डॉ. केपी कुनियाल, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मृणाल यादव, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. उषा यादव और योग एवं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉ. ज्योत्सना कुनियाल ने अपनी सेवाएं दीं। डॉक्टरों ने मरीजों का चेकअप कर उन्हें उचित दवाइयों और जीवनशैली में बदलाव को लेकर जरूरी सलाह दी।

उत्तरायण फाउंडेशन के सचिव महिपाल सिंह पिलख्वाल ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि इस कैंप में जनरल सर्जरी, हृदय रोग की जांच व सलाह, आंखों (नेत्र रोग) की जांच एवं परामर्श के साथ-साथ योग और आयुर्वेद से जुड़े मार्गदर्शन भी दिए गए।

?इस निशुल्क स्वास्थ्य शिविर को सफल बनाने में मुख्य रूप से दिनेश पिलख्वाल, चंदन पिलख्वाल,राग यादव, जगदीश पांडे, ममता मेहरा, हयात भाकुनी और राजेंद्र सिंह भोज ने सहयोग दिया।

ऋण माफी का झांसा देकर किसान से 2.75 लाख की ठगी

पथ प्रवाह, लक्सर।

कृषि ऋण माफ कराने का सपना दिखाकर एक किसान से 2.75 लाख रुपये की कथित ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने बैंक शाखा प्रबंधक समेत दो लोगों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए कोतवाली पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार कंकरखाता गांव निवासी किसान पहल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसे भरोसा दिलाया गया था कि उसका कृषि ऋण पूरी तरह माफ करा दिया जाएगा। आरोप है कि इसी विश्वास में उसने 25 अगस्त 2025 को 2.75 लाख रुपये बैंक में जमा कराए। रकम जमा करने के बाद उसे रसीद भी दी गई, जिससे उसे लगा कि ऋण माफी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। किसान का कहना है कि कई महीने बीत जाने के बावजूद उसका ऋण समाप्त नहीं हुआ। जब उसने इस संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया तो उसे लगातार टालमटोल जवाब दिए जाते रहे। कई बार बैंक और संबंधित लोगों के चक्कर लगाने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। पीड़ित के अनुसार अंततः उसने अपने अधिवक्ता के माध्यम से आरोपितों को कानूनी नोटिस भेजा। नोटिस मिलने के बाद संबंधित लोगों ने यह कहकर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया कि ऋण माफी कराना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उन्होंने उससे कोई धनराशि नहीं ली। हालांकि किसान का दावा है कि उसके पास बैंक में जमा कराई गई राशि से संबंधित सभी दस्तावेज और प्रमाण मौजूद हैं। पहल सिंह ने आरोप लगाया कि सुनियोजित तरीके से उसे भ्रमित कर 2.75 लाख रुपये हड़प लिए गए।

स्वामी/प्रकाशक वीरेन्द्र सिंह ने मुद्रक प्रमोद कुमार, जय माँ गंगा प्रिन्टर्स, राजराणा कॉम्पलैक्स निकट खाद गोदाम, जमालपुर कलां, ज्वालापुर, हरिद्वार (उत्तराखण्ड) से मुद्रित कराकर, मुख्य कार्यालयः 40 शांतिपुरम कॉलोनी जगजीतपुर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड 249408 (उत्तराखण्ड) से प्रकाशित किया। वीरेन्द्र सिंह (सम्पादक) 9411111733, डॉ सुशील शर्मा(उप संपादक) 9837906777 किसी भी वाद विवाद का निपटारा हरिद्वार में होगा। वेबसाईट- www.pathpravah.com